



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082023-248395
CG-DL-E-29082023-248395

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3666]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 29, 2023/भाद्र 7, 1945

No. 3666]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 2023/BHADRA 7, 1945

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2023

का.आ. 3827(अ).—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, केंद्र सरकार निम्नलिखित रेल प्रणालियों के भारतीय रेल की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना होने के कारण इसके संबंधित कंप्यूटर संसाधनों और इसके संलग्न अवलंबों के कंप्यूटर संसाधनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संरक्षित प्रणाली घोषित करती है, अर्थात्:-

➤ यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) और नेक्सट जेनरेशन ई टिकटिंग (एनजीईटी)

2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उप-धारा (2) के अनुसार, केंद्र सरकार संरक्षित प्रणालियों के अभिगम के लिए निम्नलिखित कर्मियों को अधिकृत करती है, अर्थात्:-

- (क) भारतीय रेल द्वारा अधिकृत पदनामित कर्मचारी।
- (ख) संविदात्मक प्रबंधित सेवा प्रदाता या तृतीय-पक्ष विक्रेता के अधिकृत टीम सदस्य जिन्हें भारतीय रेल द्वारा आवश्यकता आधारित अभिगम हेतु अधिकृत किया गया है; और
- (ग) भारतीय रेल द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर अधिकृत परामर्शदाता, विनियामक, सरकारी अधिकारी, लेखापरीक्षक और हितधारक।

3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 2019/आरबीसीसी/7/7/आईएसएससी-सीआईआई/क्रिस (पीआरएस)]

नीरज शर्मा, कार्यपालक निदेशक (पीएम)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2023

S.O. 3827(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby declares the computer resources relating to the following railway systems, being Critical Information Infrastructure of Indian Railways and the computer resources of its associated dependencies to be Protected Systems for the purposes of the said Act, namely: -

➤ **Passenger Reservation System (PRS) and Next Generation e-ticketing (NGeT).**

2. Sub-section (2) of section 70 of the Information Technology Act 2000 (21 of 2000), the Central Government authorizes the following personnel to access the Protected Systems, namely: -

- (a) any designated employee authorised by Indian Railways.
- (b) any authorised team members of contractual managed service provider or third-party vendor who have been authorised by the Indian Railways for need based access; and
- (c) any consultant, regulator, government official, auditor and stakeholder authorised by Indian Railways on case to case basis.

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2019/RBCC/7/7/ISSC-CII/CRIS (PRS)]

NEERAJ SHARMA, Executive Director(PM)